

प्रेषक,

एस0 के0 मुट्ठू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 9 सितम्बर, 2010

विषय:-ग्राम रहमतपुर, तहसील व परगना रूडकी, जिला हरिद्वार में आशा सोशल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कुल 2500 वर्ग मी0 भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-948/भूमि व्यवस्था, दिनांक-5.11.2008 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, ग्राम रहमतपुर, तहसील व परगना रूडकी, जिला हरिद्वार में आशा सोशल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कुल 2500 वर्ग मी0 भूमि कय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत, उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गयी अनापत्ति/सहमति एवं आपके द्वारा संस्तुत खसरा संख्या-193,194 एवं 195/1 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

- 3- क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (बी०एड०कालेज की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।
- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 7- प्रस्तावित भूमि का उपयोग संस्था द्वारा मात्र शैक्षणिक कार्यों हेतु ही किया जायेगा तथा इससे भिन्न कार्यों हेतु यदि भूमि का उपयोग किया जाता है तो उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी एवं संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में ली जायेगी।
- 8- संस्था द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में नियमानुसार मान्यता प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
- 9- प्रस्तावित स्थल पर, अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व, सम्बन्धित ईकाई का होगा।
- 10- किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 11- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 12- योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

13- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

14- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से जारी किये जाने वाले कार्यालय आदेश की एक प्रति अनिवार्य रूप से शासन को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0मुट्टू)

अपर मुख्य सचिव।

पृ0प0सं0-2079/समदिनांकित 2010

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- श्री कुमार गौरव, अध्यक्ष, आशा सोशल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, 351/128 सिविल लाईन्स, रुड़की जिला हरिद्वार।
- 5- निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6- प्रभारी, मीडिया केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)

अनु सचिव।